

करेंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश (संग्रह)



फरवरी
2025

Drishti, 641, First Floor,
Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry: +91-87501-87501
Email: care@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तर प्रदेश

➤ सूरजपुर आर्द्रभूमि	3
➤ उत्तर प्रदेश में क्षुद्रग्रह की खोज	4
➤ विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025	5
➤ बुंदेलखंड: सौर ऊर्जा का केंद्र	6
➤ रडार फैक्ट्री	7
➤ उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण	8
➤ लखीसराय संग्रहालय	9
➤ टूरिज्म का हब बना उत्तर प्रदेश	10
➤ वरुणा नदी में मिले प्रदूषक तत्व	12
➤ 7 नए एक्सप्रेस-वे को मंजूरी	13
➤ गुरु रविदास जयंती	14
➤ ट्रेडिग स्क्रीमर मशीन	15
➤ भारतीय कला इतिहास कॉन्ग्रेस का 32वाँ सम्मेलन	17
➤ ग्रेटर नोएडा में NSDC अंतरराष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन	17
➤ काशी तमिल संगमम	18
➤ महाकुंभ में योजनाओं की प्रदर्शनी	20
➤ हिंडन नदी	22
➤ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना	23
➤ रंग, रसायन और हस्तशिल्प पर प्रदर्शनी	24
➤ महाकुंभ से सम्बंधित भ्रामक वीडियो पर कार्रवाई	25
➤ NSSTA का 17वाँ स्थापना दिवस	26
➤ उत्तर प्रदेश बजट 2025-26	27
➤ ब्रह्मोस मिसाइल	31
➤ देश का पहला बायोपॉलिमर प्लांट	32
➤ जेवर एयरपोर्ट से जुड़ेगा गंगा एक्सप्रेस-वे	33
➤ कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य	34
➤ सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी	35
➤ गंगा जल की शुद्धता	36
➤ फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया	37
➤ उपासना स्थल अधिनियम, 1991	38
➤ महाकुंभ 2025 का समापन	40

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

उत्तर प्रदेश

सूरजपुर आर्द्रभूमि

चर्चा में क्यों ?

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सूरजपुर आर्द्रभूमि की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिये एक परियोजना विकसित की है।

मुख्य बिंदु

- प्रदूषित अपशिष्ट जल से खतरा:
 - ◆ इस आर्द्रभूमि को अत्यधिक प्रदूषित अपशिष्ट जल के अंधाधुंध तरीके से इसके नालों में छोड़े जाने के कारण गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है, जिससे इसका पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में पड़ गया है।
- तकनीकी सहायता की आवश्यकता:
 - ◆ प्राधिकरण के अनुसार, अनुसंधान संस्थान, गैर-सरकारी संगठन (NGO) और पर्यावरण विशेषज्ञ आर्द्रभूमि की सुरक्षा और पुनर्स्थापना के लिये तकनीकी सहायता प्रदान कर सकते हैं।
- पारिस्थितिक महत्त्व:
 - ◆ औद्योगिक शहर ग्रेटर नोएडा के हृदय में स्थित सूरजपुर आर्द्रभूमि एक महत्त्वपूर्ण वन्यजीव आवास के रूप में कार्य करती है, जिससे इसका संरक्षण अत्यंत आवश्यक हो जाता है।
- भौगोलिक विस्तार और विशेषताएँ:
 - ◆ यह अभयारण्य 325 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें 60 हेक्टेयर की प्राकृतिक झील भी शामिल है, जो नोएडा से लगभग 20 किमी. दूर दादरी-सूरजपुर-छलेरा (DSC) सड़क पर स्थित है।
- प्रवासी पक्षियों के लिये स्वर्ग:
 - ◆ सर्दियों के मौसम में, यह आर्द्रभूमि विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करती है, जिससे इसका पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय मूल्य बढ़ जाता है।

सूरजपुर आर्द्रभूमि

- स्थान और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार:
 - ◆ यह आर्द्रभूमि गौतमबुद्ध नगर जिले की दादरी तहसील के सूरजपुर गाँव के पास स्थित है।
 - ◆ यह ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में आता है।
- यमुना बेसिन में शहरी आर्द्रभूमि:
 - ◆ यह आर्द्रभूमि यमुना नदी बेसिन के भीतर शहरी आर्द्रभूमि का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
- पारिस्थितिक महत्त्व और हरित आवरण:
 - ◆ यह ग्रेटर नोएडा के लिये हरित फेफड़े के रूप में कार्य करता है, जो 308 हेक्टेयर जलग्रहण क्षेत्र को कवर करता है, जिसमें से 60 हेक्टेयर जलाशय के लिये समर्पित है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता (IBA):
- ◆ पक्षी संरक्षण में इसके महत्त्व के कारण बर्डलाइफ इंटरनेशनल ने इस आर्द्रभूमि को एक महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र (IBA) के रूप में वर्गीकृत किया है।
- जलपक्षियों के लिये प्रजनन एवं शीतकालीन आवास:
- ◆ यह आर्द्रभूमि **स्पॉट-बिल्ड डक**, **लेसर-व्हिसलिंग डक**, **कॉटन पिग्मी गूज** और **कॉम्ब डक** जैसे जलपक्षियों के लिये प्रजनन स्थल प्रदान करती है।
- ◆ यह **रेड-क्रेस्टेड पोचर्ड**, **फेरुजिनस पोचर्ड**, **बार-हेडेड गूज़**, **ग्रेलैंग गूज**, **कॉमन टील**, **नॉर्दन शॉवलर** और **गैडवॉल** सहित शीतकालीन जलपक्षियों का भी आश्रय है।
- विविध वन्यजीव उपस्थिति:
- ◆ समृद्ध पक्षी संख्या के अलावा, यह आर्द्रभूमि छह स्तनपायी प्रजातियों का भी आवास है, जिनमें **नीलगाय**, **भारतीय ग्रे नेवला**, **भारतीय खरगोश**, **सुनहरा सियार** और **पाँच धारी वाली गिलहरी** शामिल हैं।
- पर्यावरणीय खतरे:
- ◆ इस आर्द्रभूमि को अत्यधिक प्रदूषित अपशिष्ट जल के अँधाधुंध बहाव के कारण गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे इसके पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा उत्पन्न हो रहा है।

उत्तर प्रदेश में क्षुद्रग्रह की खोज

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (National Aeronautics and Space Administration- NASA)** ने नोएडा के कक्षा 9 के छात्र दक्ष मलिक को एक **क्षुद्रग्रह** की अनंतिम खोज के लिये मान्यता प्रदान की गई है, जिसे वर्तमान में '2023 OG40' के रूप में लेबल किया गया है।

मुख्य बिंदु

- अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह खोज परियोजना (IADP) में भागीदारी:
- ◆ दो स्कूली मित्रों के साथ, छात्र ने IADP में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय खोज सहयोग (IASC) से परिचित कराया।
- ◆ IASC, एक NASA-संबद्ध नागरिक विज्ञान पहल है, जो क्षुद्रग्रह खोज में वैश्विक भागीदारी को सक्षम बनाती है।
- ◆ यह विश्वभर के छात्रों और खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों को आकाशीय डेटा का विश्लेषण करने और वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान करने का अवसर प्रदान करता है।
- ◆ एक दुर्लभ उपलब्धि:
- ◆ प्रतिवर्ष 6,000 से अधिक प्रतिभागियों के IADP में शामिल होने के बावजूद, केवल कुछ ही नए क्षुद्रग्रहों की पहचान करने में सफल होते हैं।
- ◆ इस खोज से पहले, देश के केवल पाँच छात्रों ने कभी नामित क्षुद्रग्रह की खोज की थी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- क्षुद्रग्रह का नामकरण:
- इस उपलब्धि से **खगोलीय पिंड** का सत्यापन प्रक्रिया के पश्चात नामकरण करने का विशेषाधिकार भी प्राप्त होता है, जिसमें लगभग चार से पाँच वर्ष का समय लग सकता है।

क्षुद्रग्रह

- क्षुद्रग्रह, जिन्हें लघु ग्रह भी कहा जाता है, लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हमारे सौरमंडल के निर्माण के प्रारंभिक चरण के अवशेष हैं।
- वे मुख्यतः अनियमित आकार प्रदर्शित करते हैं, हालाँकि कुछ लगभग गोलाकार रूप भी प्रदर्शित करते हैं।
- कई क्षुद्रग्रहों के साथ छोटे चंद्रमा भी होते हैं, यहाँ तक कि कुछ के तो दो चंद्रमा भी होते हैं।
- इसके अतिरिक्त, द्वि-क्षुद्रग्रहों में एक दूसरे की परिक्रमा करने वाले दो समान आकार के चट्टानी पिंड शामिल होते हैं तथा त्रि-क्षुद्रग्रह प्रणालियाँ भी होती हैं।

विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने 2 फरवरी 2025 को पार्वती अरगा रामसर साइट, गोंडा, उत्तर प्रदेश (UP) में **विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025** समारोह का आयोजन किया।

मुख्य बिंदु

- परिचय:
 - ◆ यह दिवस **आर्द्रभूमि** के महत्त्व के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिये प्रतिवर्ष मनाया जाता है तथा यह दिवस 1971 में ईरान के रामसर में **आर्द्रभूमि पर रामसर अभिसमय** को अपनाए जाने की स्मृति को दर्शाता है।
 - ◆ 2025 का विषय/ थीम: Protecting Wetlands for our Common Future अर्थात् हमारे सामान्य भविष्य के लिये आर्द्रभूमि की रक्षा।
- नया गलियारा:
 - ◆ सरकार ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या और देवीपाटन के बीच एक नया प्रकृति-संस्कृति पर्यटन गलियारा विकसित किया जाएगा।
- अमृत धरोहर पहल:
 - ◆ **अमृत धरोहर** को जून 2023 में रामसर साइटों के संरक्षण के लिये लॉन्च किया गया था, जो चार प्रमुख घटकों अर्थात् प्रजातियों और आवास संरक्षण, प्रकृति पर्यटन, आर्द्रभूमि आजीविका और आर्द्रभूमि कार्बन पर केंद्रित है।
- खतरा:
 - ◆ आर्द्रभूमियों के लिये सबसे बड़ा खतरा औद्योगिक और मानवीय अपशिष्टों से होने वाला प्रदूषण है, जो इन पारिस्थितिकी प्रणालियों को नष्ट कर देता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स

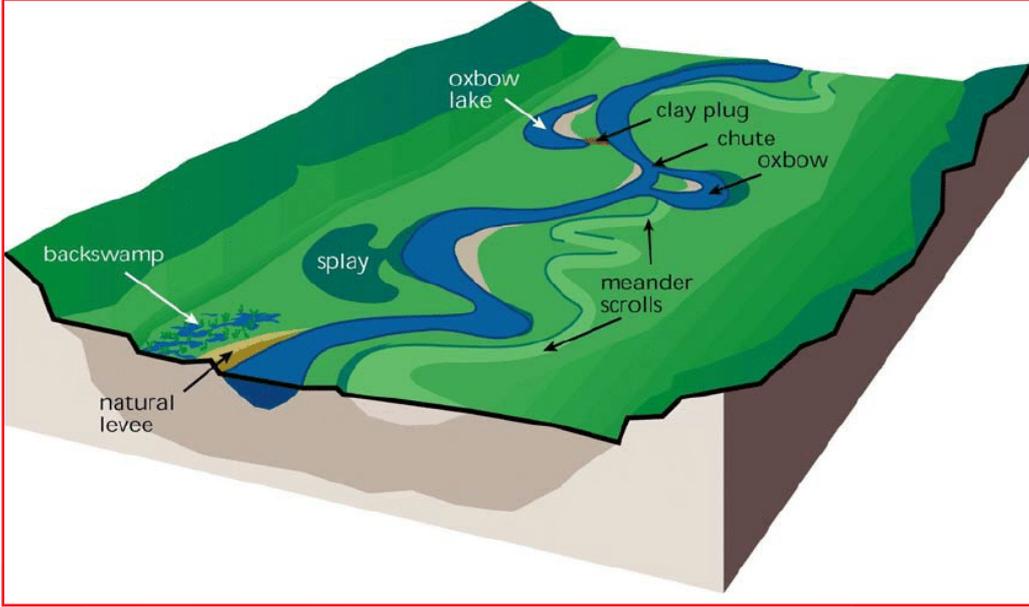


दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट:

पार्वती अरगा रामसर साइट



- परिचय : यह एक स्थायी स्वच्छ जल का वातावरण है, जिसमें **दो झीलें** अर्थात् पार्वती और अरगा शामिल हैं, जो वर्षा आधारित हैं और तराई क्षेत्र (गंगा के मैदान) में स्थित हैं।
- निकटवर्ती टिकरी वन को भी इको-पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- ऑक्सबो झीलें यू आकार की झीलें हैं, जो तब बनती हैं जब किसी नदी का घुमावदार मार्ग कट जाता है, जिससे एक अलग जल निकाय का निर्माण होता है।
- पारिस्थितिक महत्त्व: यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय **सफेद पूँछ वाले गिद्ध** (White-rumped Vulture), भारतीय गिद्ध और **लुप्तप्राय मित्र के गिद्धों** के लिये एक शरणस्थली है।
- यूरेशियन कूट्स, मैलाडर्स, ग्रेलैग गीज़, नॉर्दन पिनटेल्स और रेड-क्रेस्टेड पोचडर्स जैसे प्रवासी पक्षी सर्दियों के महीनों में इस स्थल पर आते हैं।
- आक्रामक प्रजातियाँ: इसे **आक्रामक प्रजातियों**, विशेष रूप से सामान्य **जलकुंभी** से खतरा है।
- सांस्कृतिक स्थल: यह क्षेत्र **महर्षि पतंजलि** और **गोस्वामी तुलसीदास** की जन्मस्थली जैसे सांस्कृतिक स्थलों का आवास है, जिससे धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलता है।

बुंदेलखंड: सौर ऊर्जा का केंद्र

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश **सौर ऊर्जा** के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है और **बुंदेलखंड** इस प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए ऊर्जा का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

मुख्य बिंदु

- उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा का विकास:
 - ◆ सरकार ने एक व्यापक सौर ऊर्जा नीति लागू की है, जिसके तहत सौर ऊर्जा परियोजनाओं को विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किये जा रहे हैं।
 - ◆ वर्ष 2024 में, राज्य में लगभग 1100 मेगावाट क्षमता वाले 17 सौर ऊर्जा संयंत्र चालू हो चुके हैं।
 - ◆ इन सौर संयंत्रों ने प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित किये हैं, जो उत्तर प्रदेश में अक्षय ऊर्जा विस्तार के महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव को रेखांकित करते हैं।
- बुंदेलखंड की भूमिका:
 - ◆ बुंदेलखंड अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभरा है और क्षेत्रीय विकास और रोजगार को बढ़ावा दे रहा है।
 - ◆ इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में सूर्य का प्रकाश और जलवायु परिस्थितियाँ इसे सौर ऊर्जा उत्पादन के लिये आदर्श बनाती हैं।

प्रमुख परियोजनाएँ:

- बुंदेलखंड में 4 हजार मेगावाट की सौर ऊर्जा इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। इस क्षेत्र में स्थापित 10 नए सौर संयंत्रों में से 995 मेगावाट ने काम करना शुरू कर दिया है।
- झाँसी सौर ऊर्जा परियोजना TUSCO लिमिटेड द्वारा 600 मेगावाट की परियोजना जनवरी 2025 में चालू की जाएगी। इसके साथ ही, 2024 के मध्य में 1200 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बबौना, झाँसी में फोर्थ पार्टनर एनर्जी द्वारा 100 मेगावाट का सौर संयंत्र शुरू किया गया।
- बुंदेलखंड में एक और महत्वपूर्ण विकास सन सोर्स एनर्जी सोलर ओपन एक्सेस प्रोजेक्ट है, जो राज्य के ऊर्जा ग्रिड में अतिरिक्त 135 मेगावाट का योगदान देता है।

बुंदेलखंड

- बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा में स्थित एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है।
- यह उत्तर प्रदेश के सात जिलों (झाँसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बाँदा और चित्रकूट) से मिलकर बना एक अर्ध-शुष्क क्षेत्र है।
- यह एक पर्वतमाला भी है। झाँसी बुंदेलखंड का सबसे बड़ा शहर है।
- बुंदेलखंड को पहले जेजाभुक्ति या जेजाकभुक्ति के नाम से जाना जाता था, लेकिन 14वीं शताब्दी में बुंदेलों के समय से इसे बुंदेलखंड के नाम से जाना जाने लगा।

रडार फैक्ट्री

चर्चा में क्यों ?

आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे के निकट बिज़ामई गाँव में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 400 करोड़ रुपए की लागत से रडार बनाने की फैक्ट्री स्थापित की जाएगी।

मुख्य बिंदु

- कारखाने के बारे में
 - ◆ निर्माणकर्ता: 60 हेक्टेयर में विस्तृत यह फैक्ट्री भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट:

- ◆ रडार निर्माण की सुविधा से देश की रक्षा प्रणाली में सुधार होगा, क्योंकि रडार की उच्च गुणवत्ता वाले निर्माण से सेना को बेहतर सुरक्षा और निगरानी प्रदान करने में मदद मिलेगी।
- ◆ इस फैक्ट्री के माध्यम से भारत को रडार और अन्य रक्षा उपकरणों के निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी, जिससे बाहरी देशों पर निर्भरता कम होगी।

डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DIC)

- यह केंद्र सरकार की एक प्रमुख सरकारी पहल है, जिसका उद्देश्य भारत के रक्षा उद्योग को मजबूती प्रदान करना और आत्मनिर्भर बनाना है।
- डिफेंस कॉरिडोर एक रूट होता है, जिसमें कई शहर शामिल होते हैं। इन शहरों में सैन्य उपकरणों के निर्माण के लिये इंडस्ट्री स्थापित की जाती हैं।
- महत्त्व:
 - ◆ इससे देश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, जिससे हमारा आयात कम होगा और अन्य देशों को इन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
 - ◆ यह प्रौद्योगिकियों के समन्वित विकास के माध्यम से रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगा, एमएसएमई और स्टार्ट-अप सहित निजी घरेलू निर्माताओं के विकास को बढ़ावा देगा।
- वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में देश में दो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (Defence Industrial Corridor) बनाए जाने की घोषणा की गई थी। इनमें से पहला तमिलनाडु के पाँच शहरों (चेन्नई, कोयंबटूर, होसुर, सलेम और तिरुचिरापल्ली) और दूसरा उत्तर प्रदेश के छह शहरों (अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ) में बन रहा है।

उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में जल परिवहन एवं जल पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु 'उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण' के गठन को मंजूरी दी।

मुख्य बिंदु

- जलमार्ग प्राधिकरण के बारे में:
 - ◆ जल परिवहन का विकास: इसका उद्देश्य जलमार्गों का विकास कर जल परिवहन को बढ़ावा देना है, जिससे सड़क और रेल नेटवर्क पर दबाव कम होगा।
 - ◆ जल पर्यटन का विकास: साथ ही इसके गठन से जल पर्यटन के क्षेत्र में प्रगति हो सकती है। गंगा नदी और अन्य जलमार्गों के किनारे महत्त्वपूर्ण शहर स्थित हैं, जिन्हें पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित किया जा सकता है।
 - ◆ संरचना: प्राधिकरण का अध्यक्ष परिवहन मंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा नामित जलमार्ग, जहाजरानी, नौवहन, बंदरगाह और समुद्री मामलों का विशेषज्ञ होगा।
 - उपाध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।
 - भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) के अध्यक्ष द्वारा नामित एक प्रतिनिधि भी इसका सदस्य होगा।
 - उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त इस प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- उल्लेखनीय है कि देश में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किये गए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना सहित कुल 11 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI):

- IWAI, जहाज़रानी मंत्रालय (Ministry of Shipping) के अधीन एक **सांविधिक निकाय** है।
- इसका गठन भारतीय संसद द्वारा आईडब्ल्यूएआई अधिनियम, 1985 के तहत किया गया था।
- इसका मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। जबकि क्षेत्रीय कार्यालय पटना, कोलकाता, गुवाहाटी और कोची में तथा उप-कार्यालय प्रयागराज (पूर्व में इलाहाबाद), वाराणसी, भागलपुर, रक्का और कोल्लम में हैं।

लखीसराय संग्रहालय

चर्चा में क्यों ?

6 फरवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री ने 35.8 करोड़ की लागत से बने **लखीसराय संग्रहालय** का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु

- **लखीसराय संग्रहालय के बारे में:**
 - ◆ यह बिहार का दूसरा सबसे बड़ा विश्वस्तरीय संग्रहालय है। संग्रहालय का भवन काफी सुसज्जित तरीके से बनाया गया है, जिसमें इंडोर थियेटर व आउटडोर थियेटर का भी निर्माण किया गया है।
 - ◆ लखीसराय जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खुदाई से प्राप्त **पौराणिक मूर्तियाँ, शिलालेख, मृदभांड, बौद्ध स्तूप और कीमती पत्थर** जिन्हें **अशोकधाम मंदिर** समेत अन्य स्थानों पर रखा गया था, अब इस संग्रहालय में संरक्षित किया जाएगा।
- **महत्त्व:**
 - ◆ **ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण:** संग्रहालय जिले के प्राचीन इतिहास और संस्कृति का संरक्षण करेगा, जहाँ **पुरातात्विक अवशेषों और मूर्तियों का अध्ययन और संरक्षण** किया जाएगा।
 - ◆ **पर्यटन को बढ़ावा:** संग्रहालय से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे लोग यहाँ के इतिहास और संस्कृति को जानेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।
 - ◆ **स्थानीय संस्कृति का प्रचार:** संग्रहालय लखीसराय से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्त्व को प्रस्तुत करने सहायता मिल सकती है।
- **घोषणा:** ज्ञातव्य है की लखीसराय के आसपास के क्षेत्र में पुरातात्विक अवशेषों के संरक्षण की आवश्यकता को देखते हुए लखीसराय में संग्रहालय बनाए जाने की **घोषणा वर्ष 2018 में की गई थी।**

लखीसराय जिला

- यह जिला 3 जुलाई 1994 को स्थापित किया गया था। पहले लखीसराय मुंगेर जिले में एक अनुमंडल था।
- जिले के भीतर कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों और धार्मिक स्थलों में **अशोकधाम, बरहिया के भगवती मंदिर, श्रृंगी ऋषि, जलप्या स्थान, अभयनाथ स्थान, अभिपुर पर्वत, अभिपुर के महारानी स्थान, गोविंद बाबा स्थान (मंडप) रामपुर और दुर्गा स्थान लखिसराई** आदि हैं।
- लखीसराय क्रमशः पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में मुंगेर, शेखपुरा, बेगुसराय और पटना से घिरा है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट:

टूरिज़्म का हब बना उत्तर प्रदेश

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य अपनी ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित कर पर्यटन के नए हब के रूप में अपनी पहचान बना है।

मुख्य बिंदु

- **उत्तर प्रदेश में पर्यटन:** उत्तर प्रदेश में पर्यटन का विकास न केवल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मज़बूती दे रहा है, बल्कि लाखों लोगों के लिये रोजगार के नए अवसर भी सृजित कर रहा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित कर एक नए पर्यटन हब के रूप में पहचान बनाई जा रही है।
- ◆ वर्ष 2024 में 65 करोड़ से अधिक पर्यटक उत्तर प्रदेश आए, जिन्होंने इसे भारत की पर्यटन राजधानी बना दिया।
- ◆ **अयोध्या का राम मंदिर, वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा-वृंदावन** आदि धार्मिक स्थलों ने उत्तर प्रदेश को विश्वस्तरीय आध्यात्मिक केंद्र में बदल दिया है। जिससे पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
- **स्वदेश दर्शन-2 :** केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन-2 योजना के अंतर्गत नैमिषारण्य, प्रयागराज और महोबा को विकसित किया जा रहा है।
- **महाकुंभ मेला:** प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित हो रहे इस मेले में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इस मेले नए निश्चित ही उत्तर प्रदेश को विश्वस्तर पर एक नई पहचान दिलाई है। इससे होटल व्यवसाय, ट्रांसपोर्ट, गाइड सेवाओं और हस्तशिल्प उद्योग को भी बढ़ावा मिला है।
- **पर्यटन का महत्त्व:** उत्तर प्रदेश में पर्यटन आर्थिक विकास के एक प्रमुख चालक के रूप में उभरा है। यह सबसे तेजी से आगे बढ़ते आर्थिक क्षेत्रों में से एक है और इसका व्यापार, रोजगार सृजन, निवेश, अवसरचना विकास एवं सामाजिक समावेशन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

उत्तर प्रदेश में प्रमुख दर्शनीय स्थल

स्थल	जनपद	स्थल	जनपद
ताजमहल	आगरा	संत कबीर निर्वाण स्थल	मगहर (संत कबीर नगर)
वृंदावन के मंदिर	मथुरा	माथाकुँअर बुद्ध प्रतिमा	कुशीनगर
खानकाह रशीदिया	मैनपुरी	दशावतार मंदिर	देवगढ़ (ललितपुर)
भगवान वराह मंदिर	सोरों (कासगंज)	हरिदेव जी मंदिर	मथुरा
रूमी दरवाजा	लखनऊ	लाडली जी (राधा) मंदिर	मथुरा
गोला गोकर्णनाथ मंदिर	लखीमपुर खीरी	भीतरगाँव गुप्तकालीन मंदिर	कानपुर
चक्रतीर्थ नैमिषारण्य	सीतापुर	भारद्वाज आश्रम एवं अक्षयवट	प्रयागराज
आनंद भवन	प्रयागराज	शाकंभरी देवी मंदिर	सहारनपुर
कड़कशाह बाबा की मजार	कौशांबी	दानतीर्थ (हस्तिनापुर)	मेरठ

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

बावनी इमली शहीद स्थल	फतेहपुर	झारखंडेश्वर मंदिर	हापुड़
फाँसी इमली शहीद स्थल	प्रयागराज	व्यास टीला एवं नरसिंह टीला	जालौन
शहीद स्थल छावनी	बस्ती	विंध्यवासिनी मंदिर	मिर्जापुर
कनक भवन	अयोध्या	लोधेश्वर मंदिर	बाराबंकी
सप्तमातृका की प्रतिमा	कन्नौज	भृगु मंदिर	बलिया
जे.के. मंदिर	कानपुर नगर	मुगल घाट	फर्रुखाबाद
दिगंबर जैन मूर्तियाँ (आसई किले से प्राप्त)	इटवा	औघड़नाथ मंदिर	मेरठ
शुक्ल तालाब	कानपुर देहात	जायसी स्मारक	रायबरेली
गोरखनाथ मंदिर	गोरखपुर	अशफाक उल्ला की मजार	शाहजहाँपुर
बौद्ध स्तूप	कुशीनगर एवं पिपरहवा (सिद्धार्थ नगर)	श्री दाओजी महाराज	हाथरस
बाबा सोमनाथ जी का मंदिर	देवरिया	चाइना मंदिर	श्रावस्ती
कामदगिरि पर्वत	चित्रकूट	रानी महल	झाँसी
कालिंजर दुर्ग	बाँदा	मकरबाई मंदिर	महोबा
रजा लाइब्रेरी	रामपुर	शेख सलीम चिश्ती का मकबरा	फतेहपुर सीकरी (आगरा)
शिब्ली एकेडमी	आजमगढ़	इमामबाड़ा एवं छतर मंजिल	लखनऊ
देवीपाटन (पाटेश्वरी देवी) मंदिर	बलरामपुर	लाल दरवाजा मस्जिद	जौनपुर
अरगा पार्वती मंदिर	गोंडा	हाजी वारिस अली की मजार (देवा शरीफ)	बाराबंकी
रेणुकेश्वर महादेव मंदिर	सोनभद्र	सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह	बहराइच
सीतावुंड घाट	सुल्तानपुर	कपिल मुनि आश्रम, रामेश्वरधाम मंदिर एवं भेदवुंड	फर्रुखाबाद
सीता समाहित स्थल (सीतामढ़ी)	भदोही (संत रविदास नगर)	महर्षि दधीचि आश्रम	सीतापुर
चौरासी गुंबद	कालपी (जालौन)	क्षेमकली देवी मंदिर, पद्मावती सती मंदिर, जयचंद का किला एवं हाजी शरीफ दरगाह	कन्नौज
बेल्हा देवी मंदिर	प्रतापगढ़	भरत वुंड	अयोध्या

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

एजाज अली हॉल	बिजनौर	सैयद महमूद शाह अशरफ जहाँगीर की दरगाह	अंबेडकर नगर
शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर	मुज़फ्फरनगर	सैयद शाह अब्दुल रजाक की दरगाह	बाराबंकी
धानापुर शहीद स्मारक	चंदौली	महर्षि दुर्वासा आश्रम	प्रयागराज
लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा	गाज़ीपुर	वृंतेश्वर मंदिर	बाराबंकी
श्री सनातन धर्म मंदिर	गौतमबुद्ध नगर	सलामत शाह की मज़ार	बाराबंकी
देवकली मंदिर	औरैया	राजराजेश्वरी श्रीविद्या मंदिर	उन्नाव
विक्टोरिया हॉल घंटाघर	हरदोई	दाऊजी मंदिर	मथुरा
यज्ञशाला	बागपत	तुलसी स्मारक	बाँदा

वरुणा नदी में मिले प्रदूषक तत्त्व

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के जंतु वैज्ञानिकों ने एक शोध में वरुणा नदी के जल में लगभग 1000 प्रकार के प्रदूषक तत्त्व पाए जाने की पुष्टि की।

मुख्य बिंदु

- प्रदूषक तत्त्व: शोध में यह पाया गया कि वरुणा नदी में 580 और अस्सी नदी में 349 प्रदूषण के घटक मिले हैं। इनमें टर्ट एल्काइलफेनाल, आक्टाइलफेनोल्स, ब्यूटाइलफेनोल्स, हेक्साडेसिलफेनोल्स जैसे जहरीले रसायन शामिल हैं।
- प्रभाव: ये प्रदूषक न केवल नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को बल्कि मानवीय जीवन को भी का निम्न प्रकार से खतरे में डाल रहे हैं-
 - ◆ जलीय जीवन पर असर: प्रदूषण से मछलियों और अन्य जल जीवों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जिससे उनकी मृत्यु दर बढ़ रही है और प्रजनन क्षमता घट रही है।
 - इसका जल गंगा नदी के जल को भी प्रदूषित कर रहा है।
 - ◆ जल की गुणवत्ता में कमी: प्रदूषक तत्त्व जल की गुणवत्ता को खराब करते हैं, जिससे पीने योग्य पानी की उपलब्धता में कमी हो जाती है।
 - ◆ मानवीय जीवन पर प्रभाव: प्रदूषक युक्त जल को पीने से मनुष्यों में स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं। इससे न केवल प्रजनन क्षमता में कमी हो सकती है, बल्कि ये प्रदूषक कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं।
- पूर्व रिपोर्ट: इससे पहले भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में वरुणा नदी का प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बताया गया था। वाराणसी में गंगा में मिलने से पहले वरुणा का BOD 12.40 मिलीग्राम प्रति लीटर था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट:

- वरुणा नदी का पुनरुद्धार: हालाँकि उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में वरुणा नदी के पुनरुद्धार हेतु निरंतर प्रयासरत है, जैसे- भदोही से गंगा-वरुणा संगम तक डिसिल्टिंग (सिल्ट हटाना) करना, नदी किनारे पौधरोपण कर हरित क्षेत्र बढ़ाना। इसके साथ ही, विभिन्न विकास खंडों में वेटलैंड एरिया तैयार किया जाएगा, जिससे भूजल स्तर सुधरेगा और नदी का जलस्तर सामान्य होगा।
- हाल ही में भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी के परिणामस्वरूप वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला (Smart Laboratory on Clean Rivers- SLCR) की स्थापना हुई है। इसका उद्देश्य सतत् दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए वरुणा नदी का पुनरुद्धार करना है।

वरुणा नदी के बारे में:

- यह गंगा की एक छोटी सहायक नदी है।
- यह प्रयागराज जिले के फूलपुर से निकलती है तथा वाराणसी जिले के सराय मोहना के निकट गंगा नदी से मिलती है।
- 'वाराणसी' जिले का नाम दो नदियों वरुणा और अस्सी नदियों के नाम पर रखा गया है।
- सारनाथ गंगा और वरुणा नदियों के संगम पर ही स्थित है।

7 नए एक्सप्रेस-वे को मंजूरी

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सड़क परिवहन को सुगम बनाने हेतु 7 नए एक्सप्रेस-वे के निर्माण की मंजूरी दी है।

मुख्य बिंदु

- एक्सप्रेस-वे के बारे में:
 - ◆ मुख्यमंत्री इस परियोजना पर 50 हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है।
 - ◆ ये 7 एक्सप्रेस-वे लखनऊ SCR और दिल्ली NCR के बीच उत्तर प्रदेश के 56 जिलों को आपस में जोड़ेंगे। इन सात एक्सप्रेस-वे की कुल लंबाई 866 किमी. होगी। ये एक्सप्रेस-वे आने वाले 2-3 वर्ष में बनकर तैयार हो जाएंगे।
 - ◆ यह कदम उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर करने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा।
- प्रस्तावित 7 एक्सप्रेस-वे:
 - ◆ चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे: 120 किमी लंबा यह एक्सप्रेस-वे बुंदेलखंड के विभिन्न जिलों को आपस में जोड़ने का कार्य करेगा।
 - ◆ झाँसी लिंक एक्सप्रेस-वे: इसकी लंबाई 100 किलोमीटर होगी और इसके माध्यम से बुंदेलखंड के प्रमुख जिलों को एक्सप्रेस-वे से सीधे संपर्क मिलेगा।
 - ◆ जेवर लिंक एक्सप्रेस-वे: 76 किमी. लंबा यह एक्सप्रेस-वे जेवर एयरपोर्ट को यमुना एक्सप्रेस-वे से जोड़ेगा जिससे लोग सीधे एयरपोर्ट से जुड़ सकेंगे।
 - ◆ विंध्य एक्सप्रेस-वे: इसकी लंबाई 320 किमी है और इस एक्सप्रेस-वे से उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों को बेहतर यातायात की सुविधा मिलेगी। इसमें मिर्जापुर, बनारस, जौनपुर जैसे जिले प्रयागराज से जुड़ेंगे।
 - ◆ विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस-वे: इसकी लंबाई 100 किमी है और विंध्याचल क्षेत्र को पूर्वांचल से जोड़ने के लिये मिर्जापुर से गाज़ीपुर के बीच निर्मित होगा।
 - ◆ लखनऊ लिंक एक्सप्रेस-वे: 50 किमी लंबा यह एक्सप्रेस-वे पूर्वांचल और आगरा एक्सप्रेस-वे को जोड़ेगा।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ **आगरा-लखनऊ गंगा एक्सप्रेस-वे लिंक रोड:** इस लिंक एक्सप्रेस-वे की लंबाई 90 किमी होगी, जिसे प्रयागराज से मेरठ के बीच गंगा एक्सप्रेस-वे को लखनऊ से जोड़ने के लिये बनाया जाएगा।
- **अपेक्षित लाभ:**
- **आर्थिक विकास:** इन एक्सप्रेस-वे के निर्माण से राज्य के विभिन्न हिस्सों में बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित होगी, जिससे **व्यापार और उद्योग को बढ़ावा** मिलेगा और **अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी**।
- **यात्रा में सुविधा:** यात्रा की गति और समय में काफी कमी आएगी, जिससे लोगों को यात्रा में अधिक सुविधा होगी।
- **स्थानीय विकास:** इन एक्सप्रेस-वे के बनने से उन क्षेत्रों में स्थानीय विकास होगा, जिनसे ये मार्ग गुजरेंगे। विशेषकर पिछड़े और दूर-दराज के क्षेत्रों में **अवसंरचना सुधारने में मदद मिलेगी**।
- **राज्य की कनेक्टिविटी:** इन एक्सप्रेस-वे के जरिये राज्य के विभिन्न जिलों और प्रमुख शहरों को एक दूसरे से जोड़ने से राज्य के **सडक परिवहन में सुधार** होगा।
- **रोजगार के अवसर:** इन परियोजनाओं के निर्माण और संचालन से रोजगार के कई नए अवसर सृजित होंगे।

उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस-वे नेटवर्क:

- देश में सर्वाधिक एक्सप्रेस-वे नेटवर्क उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख एक्सप्रेस-वे निम्नलिखित हैं-
 - ◆ **यमुना एक्सप्रेस-वे:** उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेस-वे
 - ◆ **गंगा एक्सप्रेस-वे:** उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे
 - ◆ आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे: उत्तर प्रदेश का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे
 - ◆ दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे
 - ◆ पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे
 - ◆ बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे
 - ◆ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे
 - ◆ लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस-वे

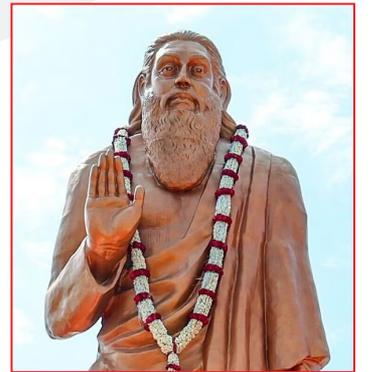
गुरु रविदास जयंती

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश में 12 फरवरी को **गुरु रविदास जयंती** मनाई गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं।

मुख्य बिंदु

- रविदास जयंती **हिंदू चंद्र कैलेंडर** के अनुसार माघ महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस वर्ष यह 12 फरवरी को मनाई गई।
- गुरु रविदास अथवा रैदास 14वीं शताब्दी के संत और उत्तर भारत में **भक्ति आंदोलन के सुधारक** थे।



दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म **वाराणसी** में एक मोची परिवार में हुआ था। एक ईश्वर में विश्वास और निष्पक्ष धार्मिक कविताओं के कारण उन्हें प्रसिद्धि मिली।
- उन्होंने अपना पूरा जीवन **जाति व्यवस्था के उन्मूलन** के लिये समर्पित कर दिया और ब्राह्मणवादी समाज की धारणा का खुले तौर पर तिरस्कार किया।
- उनके भक्ति गीतों ने **भक्ति आंदोलन पर तत्काल प्रभाव डाला** और उनकी लगभग 41 कविताओं को सिखों के धार्मिक ग्रंथ '**गुरु ग्रंथ साहिब**' में शामिल किया गया।
- संत रैदास **स्वामी रामानंद के शिष्य** थे। जबकि **मीराबाई को संत रैदास की शिष्या** कहा जाता है।
- उन्होंने रैदासिया या **रविदासिया पंथ** की स्थापना की थी।

भक्ति आंदोलन

- भक्ति आंदोलन का विकास तमिलनाडु में 7वीं और 9वीं शताब्दी के बीच हुआ।
- यह **नयनारों (शिव के भक्त) और अलवर (विष्णु के भक्त)** की भावनात्मक कविताओं में परिलक्षित होता है। इन संतों ने धर्म को एक ठंडी औपचारिक पूजा के रूप में नहीं बल्कि पूजा और पूजा करने वाले के बीच प्रेम पर आधारित एक प्रेमपूर्ण बंधन के रूप में देखा।
- समय के साथ दक्षिण के विचार उत्तर की ओर बढ़े लेकिन यह बहुत धीमी प्रक्रिया थी।
- भक्ति विचारधारा को फैलाने का एक और प्रभावी तरीका **स्थानीय भाषाओं का उपयोग** था। भक्ति संतों ने स्थानीय भाषाओं में अपने पद रचे।
- उन्होंने **संस्कृत की रचनाओं का अनुवाद भी किया** ताकि उन्हें व्यापक दर्शकों के लिये समझा जा सके।
- ◆ उदाहरणों में शामिल हैं **ज्ञानदेव ने मराठी में लिखा, कबीर, सूरदास और तुलसीदास ने हिंदी में, शंकरदेव ने असमिया को लोकप्रिय बनाया, चैतन्य और चंडीदास ने बंगाली में अपना संदेश फैलाया, मीराबाई ने हिंदी और राजस्थानी में लेखन शामिल है।**

ट्रैश स्कीमर मशीन

चर्चा में क्यों ?

प्रयागराज में **स्वच्छ भारत** के सपने को साकार करने तथा **त्रिवेणी संगम को स्वच्छ एवं निर्मल बनाए रखने के लिये ट्रैश स्कीमर मशीनें** लगाई गई हैं, जो गंगा और यमुना नदियों से प्रतिदिन 10 से 15 टन कचरा निकाल रही हैं।

मुख्य बिंदु

- त्रिवेणी संगम को स्वच्छ और शुद्ध बनाए रखने के लिये महाकुंभ से पहले वर्ष 2021 में ट्रैश स्कीमर मशीनें लगाई गई हैं।
- **ट्रैश स्कीमर मशीन:**
 - ◆ यह एक ऐसी मशीन है, जो पानी की सतह से तैरते मलबे को इकट्ठा करती है।
 - ◆ यह मशीन नदी से फूल, पत्ते, तैरता हुआ कचरा, प्लास्टिक, बोटलें आदि सभी वस्तुओं को विभिन्न तरीकों से उठाकर किनारे पर लाती है, जिनका बाद में उचित तरीकों से



दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



निपटान किया जाता है।

- ◆ इस मशीन का उपयोग नदियों, बंदरगाहों और समुद्रों को साफ करने के लिये किया जाता है।
- ◆ यह जलीय खरपतवार (जलकुंभी) को हटाने में भी मदद करती है।

जलकुंभी



- जलकुंभी, जिसे वैज्ञानिक रूप से इचोर्निया क्रैसिप्स मार्ट (पोटेडेरियासी) के नाम से जाना जाता है, एक जलीय खरपतवार है, जो भारत सहित पूरे दक्षिण एशिया में जल निकायों में आम है।
- यह कोई देशी प्रजाति नहीं है, लेकिन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान दक्षिण अमेरिका से एक सजावटी जलीय पौधे के रूप में भारत में लाई गई थी।
- यह पौधा सुंदर बैंगनी फूल पैदा करता है जिसका सौंदर्य मूल्य बहुत अधिक होता है।

स्वच्छ भारत मिशन (SBM)

- यह एक वृहत जन आंदोलन है जिसका लक्ष्य वर्ष 2019 तक स्वच्छ भारत का निर्माण करना था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सदैव स्वच्छता पर जोर देते थे क्योंकि स्वच्छता से स्वस्थ और समृद्ध जीवन की राह खुलती है।
- इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 (गांधी जयंती) के अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन की नींव रखी। यह मिशन सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को दायरे में लेता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- इस मिशन के शहरी घटक का क्रियान्वयन **आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय** द्वारा और ग्रामीण घटक का क्रियान्वयन **जल शक्ति मंत्रालय** द्वारा किया जाता है।

भारतीय कला इतिहास कॉन्ग्रेस का 32वाँ सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

भारतीय कला इतिहास कॉन्ग्रेस का 32वाँ सम्मेलन 8 से 10 फरवरी 2025 तक **इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा** में आयोजित किया गया।

मुख्य बिंदु

- **सम्मेलन के बारे में:-**
 - ◆ सम्मेलन का विषय था “**कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन**”।
 - ◆ इसका उद्देश्य **महाकाव्यों पर आधारित कलात्मक अभिव्यक्तियों के विविध रूपों को उजागर करना** था।
 - महाभारत और रामायण ने कर्तव्य, धर्म और न्याय की शिक्षाओं के साथ कई लोगों के जीवन का मार्ग प्रशस्त किया है।
 - उनके आदर्श भारत और उसके बाहर की संस्कृतियों में गूँजते हैं।
- इसका आयोजन **संस्कृति मंत्रालय** के तहत **भारतीय विरासत संस्थान, नोएडा** द्वारा किया गया था।
- **महत्त्व:**
 - ◆ सम्मेलन ने मौखिक, पाठ्य और दृश्य मीडिया के माध्यम से **महाकाव्यों पर आधारित कलात्मक अभिव्यक्तियों के विविध रूपों पर प्रकाश डाला**।
 - ◆ प्राचीन से समकालीन समय तक महाकाव्यों और उनके विभिन्न कलात्मक रूपों के प्रभाव पर चर्चा।
 - ◆ भारतीय कला में रुचि को बढ़ावा देना और इसके संरक्षण और सुरक्षा के लिये काम करना।
 - ◆ मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिये प्रयास करना।

भारतीय कला इतिहास कॉन्ग्रेस (IAHC)

- यह भारतीय कला विरासत का अध्ययन करने वाली अखिल भारतीय संस्था है।
- इसका उद्देश्य **भारतीय कला इतिहास और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर गहन शोध और विमर्श को प्रोत्साहित करना** है।
- यह संगठन भारतीय सांस्कृतिक धरोहर, **मूर्त और अमूर्त कला रूपों के संरक्षण** के लिये काम करता है।
- यह अनुभवी और युवा विद्वानों को एक मंच प्रदान करता है, ताकि वे अपनी कला संबंधित शोधों और विचारों का आदान-प्रदान कर सकें।
- इसका **मुख्यालय गुवाहाटी** में स्थित है।

ग्रेटर नोएडा में NSDC अंतरराष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और शिक्षा राज्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में **NSDC अंतरराष्ट्रीय अकादमी** का उद्घाटन किया।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
कलासंरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट:

मुख्य बिंदु

- अकादमी के बारे में:
 - ◆ यह अकादमी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है, जिसे विश्व स्तरीय कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
 - ◆ यह अकादमी भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) की प्रमुख पहल है, जो विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण और प्रमाण-पत्र प्रदान करके भारत के कार्यबल के कायाकल्प के लिये समर्पित है।
 - ◆ यह संस्थान विदेशी भाषाओं, स्वास्थ्य देखभाल, रोज़गार कौशल और विमानन सहित विभिन्न क्षेत्रों में विशेष पाठ्यक्रम प्रदान करेगी।
- उद्देश्य:
 - ◆ भारतीय युवाओं और वैश्विक रोज़गार अवसरों के बीच अंतर को पाटना।
 - ◆ उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में काम करना, जिससे जर्मनी, जापान और इज़रायल जैसे देशों की कौशल मांगों के अनुरूप विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराना।
 - ◆ नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

आरंभ

- युवाओं को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से इस योजना का शुभारंभ वर्ष 2015 में किया गया था।
- यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) का प्रमुख कार्यक्रम है तथा इसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- इस योजना ने पिछली मानक प्रशिक्षण आकलन एवं पारितोषिक (Standard Training Assessment and Reward-STAR) योजना का स्थान लिया था।

उद्देश्य

- बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, रोज़गार प्राप्त करने योग्य बनाकर जीविकोपार्जन के लिये सक्षम बनाना और इसके लिये प्रेरित करना।
- प्रमाणन प्रक्रिया में मानकीकरण को प्रोत्साहन देना और कौशल पंजीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत करना।
- वर्तमान में मौजूद श्रमबल को बढ़ाना और आवश्यकतानुसार लोगों को प्रशिक्षित करना।

काशी तमिल संगमम

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वाराणसी में काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। यह विशिष्ट आयोजन भारत की सांस्कृतिक नींव को उजागर करता है और काशी और तमिलनाडु के बीच साझा भावनात्मक और रचनात्मक बंधन पर ज़ोर देता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :



मुख्य बिंदु

- प्रेरणा और दृष्टि:
 - ◆ संगमम 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत (One India, Excellent India)' के दृष्टिकोण से प्रेरित है।
 - ◆ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह आयोजन एक भव्य आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहल का हिस्सा है जिसका उद्देश्य इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है।
 - ◆ यह आयोजन भव्य महाकुंभ 2025 समारोह के साथ एकीकृत है, जो सदियों पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाएगा और काशी तमिल संगमम के माध्यम से भारत को एकजुट करने के दृष्टिकोण को मजबूत करेगा।
- काशी, कुंभ और अयोध्या का महत्त्व:
 - ◆ यह सम्मेलन विशेष महत्त्व रखता है क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद यह पहला सम्मेलन है।
 - ◆ प्रतिनिधियों को काशी, कुंभ और अयोध्या की महानता का अनुभव करने का अवसर प्राप्त होगा।
 - ◆ मुख्यमंत्री ने भारत की सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिकता के केंद्र के रूप में काशी के ऐतिहासिक महत्त्व पर जोर दिया और तमिल साहित्य की विरासत की प्रशंसा की।
 - ◆ यह कार्यक्रम प्रतिभागियों को इस अमूल्य विरासत से पुनः जोड़ता है।
- '4S' का विषय:
 - ◆ इस वर्ष का संगमम '4S' विषय पर केंद्रित है, जो भारत की संत परंपरा (Saint Tradition), वैज्ञानिकों (Scientists), समाज सुधारकों (Social Reformers) और छात्रों (Students) को एकजुट करता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- ◆ इस विषय की प्रेरणा महर्षि अगस्त्य से ली गई है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम करने वाले ऋषि थे।
- ◆ काशी तमिल संगमम उत्तर और दक्षिण भारत के लोगों के बीच संवाद का एक प्रभावी मंच बन गया है।
- संगीत, विरासत और भक्ति:
 - ◆ केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह उत्सव गंगा के तट पर संगीत, विरासत और भक्ति को एक साथ पिरोता है।
 - ◆ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विकास और विरासत को साथ-साथ चलना चाहिये।
- केंद्र सरकार की पहल:
 - ◆ प्राचीन ग्रंथों को डिजिटल बनाने तथा अनुसंधान के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करने के लिये भारतीय ज्ञान प्रणाली के राष्ट्रीय डिजिटल भंडार की स्थापना जैसी पहलों पर प्रकाश डाला गया।
 - ◆ भारतीय भाषा पुस्तक योजना, जो पाठ्यपुस्तकों का 22 भारतीय भाषाओं में अनुवाद करेगी, छात्रों के लिये “डिजिटल महाकुंभ” का निर्माण करेगी।

काशी तमिल संगमम का महत्त्व

- काशी (उत्तर प्रदेश) और तमिलनाडु के बीच प्राचीन संबंध 15वीं शताब्दी से चला आ रहा है, जब मदुरै के आसपास के क्षेत्र के शासक राजा पराक्रम पांड्या अपने मंदिर के लिये शिवलिंग लाने के लिये काशी आए थे।
- ◆ लौटते समय वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिये रुके- लेकिन जब उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखने की कोशिश की, तो शिवलिंग को ले जाने वाली गाय ने आगे बढ़ने से मना कर दिया।
- पराक्रम पांड्या ने इसे भगवान की इच्छा समझा और वहाँ शिवलिंग स्थापित कर दिया, वह स्थान तमिलनाडु में शिवकाशी के नाम से जाना गया।
- जो भक्त काशी नहीं जा सकते थे, उनके लिये पांड्यों ने दक्षिण-पश्चिमी तमिलनाडु के तेनकाशी नामक स्थान पर काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, जो केरल के साथ राज्य की सीमा के समीप है।

महाकुंभ में योजनाओं की प्रदर्शनी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में महाकुंभ मेला में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित महत्त्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रदर्शनी आयोजित की गई।

मुख्य बिंदु

- प्रदर्शनी के बारे में:
 - ◆ यह प्रदर्शनी महाकुंभ मेला में ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार एवं ग्रामीण विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित की गई।
 - ◆ इसमें विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के बदलते परिवेश को उकेरने का प्रयास किया गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

◆ इनमें महत्वपूर्ण योजनाएँ निम्नलिखित हैं:



- **मनरेगा योजना** के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्य जैसे **अमृत-सरोवर**, **सोक पिट**, **रेन वाटर हर्वेस्टिंग**, **नालियों का निर्माण**, **वृक्षारोपण**, **पंचायत भवन** आदि कराए गए। इन कार्यों से ग्रामीण क्षेत्र का स्वरूप बदला और विकास हुआ।
- **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन** के **सरस हाट** के माध्यम से महिलाओं के उत्पादों को प्रमोट कर उनकी आजीविका को संवर्धित किया गया। **बीसी सखी** और **ड्रोन सखी** जैसे कार्यक्रमों से महिलाओं के **आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुधार** दिखाया गया।
- **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)** और **मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)** के तहत **मॉडल आवासों** से ग्रामीण क्षेत्रों में आवास का बदलता स्वरूप और हर परिवार को अपना पक्का मकान देने का लक्ष्य पूरा किया गया।
- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** के तहत 250 से अधिक आबादी वाली ग्रामीण क्षेत्रों को सभी मौसमों में चलने योग्य सड़कों से जोड़ा गया है।
- **एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन प्रणाली**
- **स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण**
- मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में **अमृत-सरोवर**, **सोखा गड्ढा**, **वर्षा जल संचयन**, **नालियों का निर्माण**, **वृक्षारोपण** आदि विभिन्न विकास कार्य कराए गए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर बदल गई और विकास को बढ़ावा मिला।

सरस हाट के बारे में:

- यह सामान्य रूप से ग्रामीण भारत और विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के जीवन को बदलने का एक कार्यक्रम है।
- मेले के दौरान, **ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों** और कारीगरों को शिक्षित करने के लिये उत्पाद पैकेजिंग और डिजाइन, संचार कौशल, सोशल मीडिया प्रचार और **बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग** पर कार्यशालाएँ आयोजित की जाएंगी।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट:

आयोजक:

- यह **ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD)** के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) द्वारा **पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी (CAPART)** की उन्नति परिषद द्वारा आयोजित एक पहल है।
- CAPART ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है, जो सरकार और गैर-सरकारी संगठनों (NGO) के बीच इंटरफेस के लिये है जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना चाहते हैं।

उद्देश्य:

- ग्रामीण महिला **स्वयं सहायता समूहों (SHG)** को एक मंच पर लाना ताकि वे अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकें, अपने उत्पाद बेच सकें और थोक खरीदारों के साथ संबंध बनाने में उनकी मदद कर सकें।
- सरस आजीविका मेले में भागीदारी के माध्यम से, इन ग्रामीण स्वयं सहायता समूह महिलाओं को शहरी ग्राहकों की मांग और रुचि को समझने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त होगा।

कुंभ मेले के बारे में

- वर्ष 2025 में महाकुंभ मेला प्रयागराज में **13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जा रहा है**, जिसमें आध्यात्मिक शुद्धि, सांस्कृतिक उत्सव एवं एकता के प्रतीक के रूप में लाखों तीर्थयात्री प्रतिदिन आ रहें।
- 'कुंभ' शब्द की उत्पत्ति 'कुंभक' (अमरता के अमृत का पवित्र घड़ा) धातु से हुई है।
- यह तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम है जिसके दौरान प्रतिभागी पवित्र नदी में स्नान या डुबकी लगाते हैं। यह समागम 4 अलग-अलग जगहों पर होता है, अर्थात्:
 - ◆ हरिद्वार में गंगा के तट पर।
 - ◆ उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर।
 - ◆ नासिक में गोदावरी (दक्षिण गंगा) के तट पर।
 - ◆ प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक अदृश्य **सरस्वती** के संगम पर

कुंभ के विभिन्न प्रकार:

- • कुंभ मेला 12 वर्षों में 4 बार मनाया जाता है।
- • हरिद्वार और प्रयागराज में अर्द्धकुंभ मेला हर छठे वर्ष आयोजित किया जाता है।
- • महाकुंभ मेला 144 वर्षों (12 'पूर्ण कुंभ मेलों' के बाद) के बाद प्रयाग में मनाया जाता है।
- • प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ (जनवरी-फरवरी) महीने में माघ कुंभ मनाया जाता है।

हिंडन नदी**चर्चा में क्यों ?**

हाल ही में **गाज़ियाबाद में हिंडन नदी** में भारी मात्रा में गाद और धार्मिक सामग्री डाल दी गई है, जो पहले से ही प्रदूषित नदी को और अधिक प्रदूषित कर रहा है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट:

मुख्य बिंदु

- उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने नदी के प्रदूषित होने का कारण कुप्रबंधन और पानी की गुणवत्ता पर ध्यान न देना तथा अनेक अनुपचारित नालों का नदी में गिरना बताया है।
- घुलित ऑक्सीजन (DO) 1.43 से 4.22 मिलीग्राम/लीटर के बीच है, जबकि जलीय जीवन के लिये न्यूनतम DO 4 मिलीग्राम/लीटर होना चाहिये।
 - ◆ कुल कोलीफॉर्म का स्तर 260,000 से 380,000 MPN/100ML तक है, जबकि मानक सीमा 1,000 MPN/100 ML है।
 - ◆ उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) ने नदी की जल गुणवत्ता को 'ई' श्रेणी में रखा, जिसका अर्थ है कि पानी सिर्फ सिंचाई, औद्योगिक शीतलन और नियंत्रित अपशिष्ट निपटान के लिये उपयुक्त है।
- वर्ष 2015 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने हिंडन नदी को "मृत नदी" घोषित कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि इसमें प्रदूषण का स्तर अत्यधिक है, विभिन्न भागों में यह स्नान के लिये अनुपयुक्त है।

हिंडन नदी के बारे में:

- यह नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 400 किमी. तक बहती हुई नोएडा में यमुना नदी में मिल जाती है।
- अतः यह यमुना नदी की एक सहायक नदी है।
 - ◆ यह एक मानसून पोषित नदी है।
 - ◆ इसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 7,083 वर्ग किमी. है।
- काली (पश्चिम) नदी और कृष्णा नदी हिंडन नदी की मुख्य सहायक नदियाँ हैं।
- इसी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, जो 2500 ईसा पूर्व तक पुराने हैं।
- गाज़ियाबाद और नोएडा इस नदी के किनारे पर ही स्थित हैं।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विवादित बयान के बाद उन्हें पद से हटाने के लिये 55 सदस्यों की ओर से हस्ताक्षरित महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया गया है।

मुख्य बिंदु

- मुद्दे के बारे में:
 - ◆ न्यायाधीश ने विगत वर्ष दिसंबर में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में कथित तौर पर कुछ सांप्रदायिक टिप्पणियाँ की थीं।
 - ◆ राज्यसभा में विपक्ष के 55 सांसदों ने न्यायाधीश जाँच अधिनियम, 1968 के तहत न्यायाधीश को उनके कथित कदाचार के लिये न्यायाधीश के पद से हटाने के लिये प्रस्ताव पेश करने हेतु नोटिस दिया है।
- न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया:
 - ◆ अनुच्छेद 124 और 218 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा "सिद्ध दुर्व्यवहार" या "अक्षमता" के आधार पर हटाया जा सकता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
कलासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ हटाने के लिये संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है:
 - सदन की कुल सदस्यता का बहुमत।
 - उसी सत्र में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई का विशेष बहुमत।
- ◆ संविधान में “सिद्ध कदाचार” और “अक्षमता” शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया है।
 - सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या के अनुसार दुर्व्यवहार में जानबूझकर किया गया कदाचार, भ्रष्टाचार, निष्ठा की कमी या नैतिक अधमता शामिल है।
 - अक्षमता से तात्पर्य न्यायिक कार्यों में बाधा डालने वाली शारीरिक या मानसिक स्थिति से है।
- न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 के अंतर्गत प्रक्रिया:
- प्रस्ताव की सूचना:
 - ◆ इसके लिये कम से कम 50 राज्यसभा सदस्यों या 100 लोकसभा सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।
 - ◆ परामर्श के बाद अध्यक्ष या स्पीकर यह निर्णय लेते हैं कि प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए या नहीं।
- गठित जाँच समिति:
 - ◆ यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो न्यायाधीशों और एक प्रतिष्ठित न्यायविद सहित तीन सदस्यीय समिति गठित की जाती है।
 - ◆ समिति आरोपों की जाँच करती है:
 - यदि न्यायाधीश को दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो प्रस्ताव निरस्त हो जाता है।
 - यदि दोषी पाया जाता है तो समिति की रिपोर्ट मतदान के लिये संसद में भेजी जाती है।
- संसदीय अनुमोदन:
 - ◆ राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीश को हटाने के लिये दोनों सदनों को विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा।

रंग, रसायन और हस्तशिल्प पर प्रदर्शनी

चर्चा में क्यों ?

ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में हस्तशिल्प, रंग और रसायन तथा परिधान प्रौद्योगिकी पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

मुख्य बिंदु

- आयोजन के बारे में:
 - ◆ इस प्रदर्शनी का आयोजन भारत टेक्स 2025 के तहत किया गया, जबकि वृहद् कार्यक्रम भारत मंडपम, नई दिल्ली में 14 से 17 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया।
 - ◆ यह प्रदर्शनी उद्योगों को नए व्यापारिक अवसर, उत्कृष्टता प्रदर्शन, स्थायित्व और नवाचार के जरिये समग्र विकास और प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देती है।
- इसमें आयोजित कार्यक्रम चार प्रमुख विषयों पर केंद्रित थे:
 - ◆ गारमेंट टेक्नोलॉजी एक्सपो (GTE) 2025 - अत्याधुनिक मशीनरी, प्रक्रियाओं और समाधानों का प्रदर्शन।
 - ◆ डाईकेम वर्ल्ड भारत टेक्स 2025 - प्रकृति अनुकूल रंगों, रसायनों और कच्चे माल पर केंद्रित प्रदर्शनी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :



- ◆ हस्तनिर्मित उत्पाद प्रदर्शनी - हस्तनिर्मित वस्त्रों की प्रदर्शनी।
- ◆ इंडिया सोर्सिंग कॉन्वलेव (ISC) - सोर्सिंग कंसल्टेंट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित सम्मेलन।

महाकुंभ से सम्बंधित भ्रामक वीडियो पर कार्रवाई

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश पुलिस ने महाकुंभ 2025 को लेकर सोशल मीडिया पर शेयर किये जा रहे भ्रामक वीडियो को लेकर सख्त कार्रवाई की है।

मुख्य बिंदु

- मुद्दे के बारे में:
 - ◆ पिछले एक महीने में 53 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
 - ◆ इन अकाउंट्स के माध्यम से महाकुंभ से जुड़ी गलत जानकारी और गुमराह करने वाले वीडियो पोस्ट किये गए थे।
 - ◆ मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस और साइबर एजेंसियाँ इन गलत खबरों पर नज़र रख रही हैं, ताकि ऐसी भ्रामक जानकारी को फैलने से रोका जा सके।
- लोगों पर प्रभाव:
 - ◆ इन घटनाओं में झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाने की कोशिश की गई थी। इन गलत सूचनाओं का असर लोगों के मन में भ्रम और डर उत्पन्न करता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट:

- ◆ साथ ही समाज में तनाव और असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न होता है।

सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ संबंधी नियम-कानून

- उल्लेखनीय है कि भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पहले से ही **सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2008** के दायरे में आते हैं।
- हालांकि भारत में फेक न्यूज़ को रोकने के लिये कोई विशेष कानून नहीं है। परंतु भारत में अनेक संस्थाएँ हैं, जो इस संदर्भ में कार्य करती हैं।
- ◆ **प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया** एक ऐसी ही नियामक संस्था है जो समाचार पत्र, समाचार एजेंसी और उनके संपादकों को उस स्थिति में चेतावनी दे सकती है यदि यह पाया जाता है कि उन्होंने पत्रकारिता के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है।
- ◆ **न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (NBA)** निजी टेलीविजन समाचार और करेंट अफेयर्स के प्रसारकों का प्रतिनिधित्व करता है एवं उनके विरुद्ध शिकायतों की जाँच करता है।
- ◆ **ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंफ्लेंट काउंसिल (BCCC)** टीवी ब्रॉडकास्टर्स के खिलाफ आपत्तिजनक टीवी कंटेंट और फर्जी खबरों की शिकायत स्वीकार करती है और उनकी जाँच करती है।

NSSTA का 17वाँ स्थापना दिवस

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी (NSSTA) ने 13 फरवरी, 2025 अपना 17वाँ स्थापना दिवस मनाया।

मुख्य बिंदु

- **स्थान:**
 - ◆ यह दिवस महालनोबिस ऑडिटोरियम, NSSTA, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में मनाया गया।
- **विषय:**
 - ◆ इसका विषय था: “सांख्यिकीय उत्कृष्टता के माध्यम से शासन को सशक्त बनाना- क्षमता विकास और सहयोग के 17 वर्ष”।
- **उद्देश्य:**
 - ◆ सांख्यिकीविदों और क्षेत्र के अधिकारियों को उन्नत कार्यप्रणाली से युक्त करना, उच्च गुणवत्ता वाले डाटा संग्रह को सुनिश्चित करना, साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण का समर्थन करना।

राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी (NSSTA):

परिचय:

- ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थित यह संस्था **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन** एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण संस्था है।
- इसकी स्थापना जनवरी 2009 में की गई थी।

उद्देश्य

- इसका प्रमुख उद्देश्य भारत में **सांख्यिकीय प्रणाली को मज़बूत करना और सांख्यिकीय क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना** है।
- इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और अन्य संबंधित व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट:



महत्त्व

- सरकारी अधिकारियों और सांख्यिकीविदों को **डाटा संग्रहण और विश्लेषण** में दक्ष बनाता है।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांख्यिकी के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों और विधियों से प्रशिक्षुओं को परिचित कराता है।
- सांख्यिकी विज्ञान से जुड़े नए अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और सरकारी योजनाओं में आँकड़ों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने में सहायक।
- विभिन्न **राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ** मिलकर सांख्यिकीय प्रशिक्षण और अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है।

उत्तर प्रदेश बजट 2025-26

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 फरवरी 2025 को वित्त वर्ष 2025-26 के लिये 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ रुपए का बजट **विधानसभा** में पेश किया।

मुख्य बिंदु

- **बजट के बारे में**
 - ◆ सरकार ने बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं व बच्चों का विशेष ध्यान रखा है।
 - ◆ बजट में समाज के हर वर्ग – गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, महिला, युवा और आम लोगों की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास है। यह वास्तव में जनहित का बजट है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- ◆ मुख्यमंत्री नए बजट को सनातन धर्म के सर्वे भवन्तु सुखिन: की अवधारणा के अनुरूप बताया है।
- ◆ कुल बजट: 8,08,736 करोड़ रुपए का है, जो वित्त वर्ष 2024-25 के बजट से 9.8% अधिक है।
- ◆ बजट में 28 हजार 478 करोड़ 34 लाख रुपए (28,478.34 करोड़ रुपए) की नई योजनाएँ सम्मिलित की गई हैं।
- ◆ उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 93 हजार रुपए से अधिक है।
- ◆ भारतीय रिज़र्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, सभी राज्यों के बीच कर प्राप्तियों (Tax Collection) में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी देश में सबसे अधिक है।
- प्रदेश की GDP
 - ◆ वित्त वर्ष 2017-18 में प्रदेश की जी.डी.पी. 12.89 लाख करोड़ रुपए थी, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 27.51 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है।
 - ◆ वर्ष 2023-24 में भारत देश की जी.डी.पी. की वृद्धि दर 9.6 प्रतिशत थी जबकि उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर 11.6 प्रतिशत रही है।
 - ◆ प्रदेश का राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 2.97 प्रतिशत है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक FRBM अधिनियम में निर्धारित 3.5 प्रतिशत की सीमा से कम है।

प्राप्तियाँ और व्यय का सारांश

विवरण	राशि (रुपए में)
कुल प्राप्तियाँ	7,79,242.65
राजस्व प्राप्तियाँ	6,62,690.93
पूँजीगत प्राप्तियाँ	1,16,551.72
कर राजस्व	5,50,172.21
- स्वयं का कर राजस्व	2,95,000
- केंद्रीय करों में राज्य का अंश	2,55,172.21
कुल व्यय	8,08,736.06
राजस्व लेखे का व्यय	5,83,174.57
पूँजी लेखे का व्यय	2,25,561.49

क्षेत्रवार विवरण

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME):
 - ◆ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान वित्त वर्ष 2024-25 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करना।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट:

- ◆ वित्त वर्ष 2025-26 में इस योजना हेतु 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित।
- ◆ **मुख्यमंत्री युवा स्वरोज्जगार योजना** हेतु 225 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग:**
 - ◆ **हथकरघा उद्योग** प्रदेश का सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है।
 - ◆ प्रदेश में लगभग 1.91 लाख हथकरघा बुनकर एवं लगभग 80 हजार हाउस होल्ड हैं।
 - ◆ प्रदेश में 2.58 लाख **पावरलूम** कार्यरत हैं जिसके माध्यम से लगभग 5.50 लाख पावरलूम बुनकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं।
 - ◆ **पीएम मित्र योजना** के तहत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
 - ◆ उत्तर प्रदेश वस्त्र गारमेंटिंग पालिसी, 2022 के क्रियान्वयन हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
 - ◆ PM मित्र टेक्सटाइल योजना के लिये 150 करोड़ रुपए।
 - ◆ वस्त्र गारमेंटिंग योजना के लिये 150 करोड़ रुपए।
 - ◆ **अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम योजना** के लिये 400 करोड़ रुपए।
 - ◆ **डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर** के लिये 461 करोड़ रुपए का बजट।
- **अवस्थापना और विकास:** अवस्थापना विकास के लिये 22% राशि आवंटित।
 - ◆ **जल विद्युत परियोजना** के लिये 3953 करोड़ रुपए।
 - ◆ एक्सप्रेस-वे के लिये 900 करोड़ रुपए (आगरा एक्सप्रेस-वे को गंगा एक्सप्रेस-वे से जोड़ने हेतु)।
 - ◆ **गंगा एक्सप्रेस-वे** का विस्तार हरिद्वार तक किया जाएगा।
 - ◆ **मथुरा-वृंदावन बांकेबिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण** के लिये 100 करोड़ रुपए।
 - ◆ मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना हेतु मध्यम श्रेणी की **इलेक्ट्रिक बसों** के क्रय हेतु 100 करोड़ रुपए तथा चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
 - ◆ **जल जीवन मिशन** के लिये 4500 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
- **शिक्षा और उच्च शिक्षा:**
 - ◆ शिक्षा के लिये 13% राशि आवंटित।
 - ◆ 22 नए प्राथमिक स्कूलों के लिये 25 करोड़ रुपए।
 - ◆ **पीएम श्री योजना** के लिये 300 करोड़ रुपए।
 - ◆ डिजिटल लाइब्रेरी के लिये 454 करोड़ रुपए (गांवों में)।
 - ◆ पॉलिटेक्निक स्मार्ट क्लास रूम के लिये 10 करोड़ रुपए।
 - ◆ हायर एजुकेशन में छात्राओं को लाभ मिलेगा, स्कूटी योजना के तहत मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी।
 - ◆ गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय (2025 में पूरा होगा)।
 - ◆ बलिया और बलरामपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज की घोषणा।
- **कृषि और ग्रामीण विकास:**
 - ◆ कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिये 11% राशि आवंटित।
 - ◆ गाँवों में नए स्टेडियम के लिये 125 करोड़ रुपए।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट:

- ◆ **मत्स्य संपदा योजना** के लिये 195 करोड़ रुपए।
- ◆ **स्वच्छ भारत मिशन** के लिये 425 करोड़ रुपए।
- **महिला एवं बाल विकास:**
 - ◆ **रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना** के लिये 400 करोड़ रुपए।।
 - ◆ पात्रता के आधार पर स्कूटी प्रदान की जाएगी।
 - ◆ निराश्रित महिला पेंशन योजना के पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन भुगतान के लिये 2980 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
 - ◆ **मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना** हेतु 700 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था।
 - ◆ कोविड के दौरान संचालित उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री **बाल सेवा योजना** के लिये 252 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित।
 - ◆ पुष्ताहार कार्यक्रम के लिये मूल्य **समन्वित बाल विकास** के लिये लगभग 4119 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
 - ◆ मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव।
- **सामाजिक विकास और जन कल्याण:**
 - ◆ **PM आवास योजना** के लिये 4848 करोड़ रुपए।
 - ◆ 2025 में छात्रों को टैबलेट वितरण की योजना।
 - ◆ **वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना** के लिये (1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन) 8105 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
 - ◆ सभी वर्गों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान की **मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना** हेतु 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित।
 - ◆ वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवासीय गृह संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता प्रदान किये जाने हेतु 60 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित।
 - ◆ अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु लगभग 6 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित।
 - ◆ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान “पीएम- जनमन” के अन्तर्गत विशेष रूप से कमजोर जन जातीय समूहों का समग्र विकास किया जाना है।
 - ◆ अल्पसंख्यक समुदाय के विकास एवं उत्थान हेतु वित्त वर्ष 2025-26 में 1998 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था।
 - ◆ कृषकों को दुर्घटनावश मृत्यु/अनैतिकता की स्थिति में आर्थिक सहायता की मुख्यमंत्री आकस्मिकता कल्याण योजना 1050 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
- **स्वास्थ्य:**
 - ◆ चिकित्सकीय और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये 6% राशि आवंटित।
 - ◆ **आयुष्मान कार्ड बनाने में पूरे देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।**
 - ◆ राजकीय औषधि कॉलेज की स्थापना और वाराणसी में राजकीय होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज की स्थापना।
 - ◆ बलिया और बलरामपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा।
- **साइबर सुरक्षा और तकनीकी विकास:**
 - ◆ साइबर सुरक्षा के लिये 3 करोड़ रुपए।
 - ◆ ‘**आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी**’ की स्थापना की घोषणा।
 - ◆ ‘**टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क**’ की स्थापना की योजना।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- ◆ लखनऊ में AI सिटी बनाने के लिये 5 करोड़ रुपए का बजट।
- ◆ ICT लैब और स्मार्ट सिटी की योजना
- ◆ सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की योजना
- नगर निकाय और शहरों का विकास:
 - ◆ प्रत्येक नगर निकाय के लिये 2.5 करोड़ रुपए का बजट।
 - ◆ 58 नगर निकायों का विकास किया जाएगा।
 - ◆ NCR की तरह स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) बनेगा, जिसमें 6 जिले – लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी शामिल होंगे।
- पर्यटन और सांस्कृतिक विकास:
 - ◆ मथुरा-वृंदावन कॉरिडोर के लिये 100 करोड़ रुपए।
 - ◆ अयोध्या में पर्यटन विकास के लिये 150 करोड़ रुपए।
 - ◆ चित्रकूट और मथुरा में पर्यटन विकास के लिये 125 करोड़ रुपए।
 - ◆ जन उपयोगी मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिये 30 करोड़ रुपए।
- वन एवं पर्यावरण
 - ◆ वर्तमान प्रदेश में वृक्षाच्छादन प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.96 प्रतिशत हो गया है।
 - ◆ उत्तर प्रदेश वनावरण व वृक्षाच्छादन में वृद्धि के मामले में पूरे देश में दूसरे स्थान पर है।
 - ◆ प्रदेश में वर्ष 2018 में बाघों की संख्या 173 से वर्ष 2022 में बाघों की संख्या 205 हो गयी है।
 - ◆ गोरखपुर में देश का पहला गिब्द जनजाति केंद्र स्थापित किया गया।
 - ◆ गोरखपुर में उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना होगी।

ब्रह्मोस मिसाइल

चर्चा में क्यों ?

लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के विनिर्माण का कार्य इस वर्ष मई-जून में शुरू हो जाएगा, जो भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिये एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

मुख्य बिंदु :

- विनिर्माण के बारे में:
- रक्षा मंत्री के अनुसार लखनऊ में रक्षा उपकरणों के साथ ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण किया जाएगा।
- मिसाइल को विनिर्माण इकाई तक ले जाने के लिए रेलवे ट्रैक भी बनाया जाएगा।
- इस परियोजना में: रूसी वैज्ञानिक भी भारत के साथ काम करेंगे। यह उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे का एक हिस्सा है।
- ज्ञातव्य है कि भारत के दो राज्यों उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा गलियारा के जरिये रक्षा विनिर्माण केंद्र स्थापित किये जा रहे हैं।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में

- **ब्रह्मोस मिसाइल** जिसकी रेंज 290 किमी. है, भारत-रूस का एक संयुक्त उद्यम है और यह मैक 2.8 (ध्वनि की गति से लगभग तीन गुना) की शीर्ष गति के साथ दुनिया की सबसे तेज़ क्रूज़ मिसाइल है।
- ◆ ब्रह्मोस का नाम **ब्रह्मपुत्र** (भारत) और **मोस्कवा** (रूस) नदियों के नाम पर रखा गया है।
- यह दो चरणों वाली मिसाइल (पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन और दूसरे चरण में तरल रैमजेट) है।
- यह एक **मल्टीप्लेटफॉर्म मिसाइल** है यानी इसे ज़मीन, हवा और समुद्र से लॉन्च किया जा सकता है तथा सटीकता के साथ **बहु-क्षमता वाली मिसाइल** है जो मौसम की स्थिति के बावजूद दिन और रात दोनों समय काम करती है।
- यह **“फायर एंड फॉरगेट्स”** सिद्धांत पर काम करती है यानी लॉन्च के बाद इसे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है।
- वियतनाम, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल के अन्य संभावित ग्राहकों में से हैं।



देश का पहला बायोपॉलिमर प्लांट

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 22 फरवरी 2025 को **लखीमपुर खीरी** के कुंभी में देश के पहले **बायोपॉलिमर संयंत्र** का शिलान्यास किया।

मुख्य बिंदु

- संयंत्र के बारे में:
 - ◆ यह बायोपॉलिमर संयंत्र **बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड** द्वारा 2,850 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- ◆ यह जैविक तरीके से पॉलिमर उत्पादन का कार्य करेगा। इससे पर्यावरण के अनुकूल औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिलेगा।
- उद्देश्य:
 - ◆ इसका मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक की जगह बायोपॉलिमर का उपयोग करके पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है।
 - ◆ यह संयंत्र आत्मनिर्भर भारत और पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को साकार करेगा।
- लाभ:
 - ◆ संयंत्र द्वारा उत्पादित बोतलें, प्लेट, कप, थैले आदि पूरी तरह से 'डिस्पोजिबल' होंगे और इस्तेमाल के बाद मात्र तीन महीने में नष्ट हो जाएंगे।
 - ◆ प्लास्टिक की बजाए बायोपॉलिमर का इस्तेमाल करने से पर्यावरण पर दबाव कम होगा।
 - ◆ इस संयंत्र से 'मेक इन इंडिया' के तहत देश में बायोपॉलिमर उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
 - ◆ इससे प्रदेश में व्यापार और निवेश को गति मिलेगी।

मेक इन इंडिया पहल:

- परिचय:
 - ◆ वर्ष 2014 में लॉन्च किये गए मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य देश को एक अग्रणी वैश्विक विनिर्माण और निवेश गंतव्य में बदलना है।
 - ◆ इसका नेतृत्व उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade- DPIIT), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है।
 - ◆ यह पहल दुनिया भर के संभावित निवेशकों और भागीदारों को 'न्यू इंडिया' की विकास गाथा में भाग लेने हेतु एक खुला निमंत्रण है।
 - ◆ मेक इन इंडिया ने 27 क्षेत्रों में पर्याप्त उपलब्धियाँ हासिल की हैं। इनमें विनिर्माण और सेवाओं के रणनीतिक क्षेत्र भी शामिल हैं।
- उद्देश्य:
 - ◆ विनिर्माण क्षेत्र की संवृद्धि दर को बढ़ाकर 12-14% प्रतिवर्ष करना।
 - ◆ वर्ष 2022 तक (संशोधित तिथि 2025) विनिर्माण से संबंधित 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजित करना।
 - ◆ वर्ष 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान बढ़ाकर 25% करना।
 - ◆ नए औद्योगीकरण के लिये विदेशी निवेश को आकर्षित करना और चीन से आगे निकलने के लिये भारत में पहले से मौजूद उद्योग आधार का विकास करना।

जेवर एयरपोर्ट से जुड़ेगा गंगा एक्सप्रेस-वे

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NIA), जिसे जेवर एयरपोर्ट भी कहा जाता है, को गंगा एक्सप्रेस-वे से जोड़ने की घोषणा की।

मुख्य बिंदु

- मुद्दे के बारे में:
 - ◆ गंगा एक्सप्रेस-वे को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने के लिये 76 किमी. लंबा एक नया लिंक एक्सप्रेसवे बुलंदशहर होते हुए बनाया जाएगा।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट:

- ◆ सरकार ने बजट में इस परियोजना के लिये 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है।
- ◆ यह लिंक एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेस-वे के जरिये 24 किलोमीटर पहले ही जुड़ जाएगा।
- ◆ इस पूरी परियोजना की अनुमानित लागत 4415 करोड़ रुपए है।

● लाभ:

- ◆ इस एक्सप्रेस-वे के बनने से मेरठ, बुलंदशहर के लोग कम समय में सीधे जेवर एयरपोर्ट तक पहुँच सकेंगे। साथ ही पूरवाँ चल और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे से आने वाले लोगों को भी इस एक्सप्रेस-वे का लाभ मिलेगा।
- ◆ इससे व्यापारिक और औद्योगिक विकास में गति आएगी।
- ◆ बेहतर कनेक्टिविटी से पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा।

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट

- यह एयरपोर्ट विश्व का चौथा सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उत्तर प्रदेश का 5वाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। वहीं दिल्ली एनसीआर में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) के बाद यह दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा।
- नोएडा एयरपोर्ट को ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल (Zurich Airport International AG) द्वारा तैयार किया जा रहा है।
- इस एयरपोर्ट पर स्टेट ऑफ आर्ट MRO (Maintenance, Repair & Overhauling) सर्विस भी उपलब्ध होगी। एयरपोर्ट को इस प्रकार से डिजाइन किया गया कि इससे ऑपरेटिंग खर्चों को कम रखा जा सकेगा एवं यात्रियों के ट्रांसफर प्रोसेस को शीघ्रता से किया जा सकेगा।
- आसपास की सड़कों, हाईवे जैसे यमुना एक्सप्रेस-वे, वेस्टर्व फेरिफेरल, ईस्टर्न फेरिफेरल, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे और दूसरे हाईवे को भी एयरपोर्ट से सीधा कनेक्ट किया जाएगा। एयरपोर्ट को दिल्ली-वाराणसी के बीच प्रस्तावित हाई स्पीड रेल से भी जोड़ा जाएगा, जिससे दिल्ली और नोएडा एयरपोर्ट की दूरी 21 मिनट में पूरी की जा सकेगी।
- नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर्यावरण के लिहाज से देश का पहला नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट होगा। पास की जमीन पर पेड़ों को लगाकर फारेस्ट पार्क तैयार किया जाएगा।

गंगा एक्सप्रेस-वे

- गंगा एक्सप्रेस-वे मुंबई-नागपुर एक्सप्रेस-वे के बाद देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे है।
- यह 594 किलोमीटर की अनुमानित लंबाई वाला एक महत्वाकांक्षी पहल है।
- राज्य को पूर्व से पश्चिम तक जोड़ने वाला यह एक्सप्रेस-वे 12 जिलों के 518 गाँवों से होकर गुजरेगा, जिससे मेरठ और प्रयागराज के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
- गंगा एक्सप्रेस-वे केवल एक परिवहन लिंक नहीं है, बल्कि अपने एडवेंचर लैंडस्केप को आधुनिक बनाने के लिये उत्तर प्रदेश के विस्तार का एक प्रमाण है।

कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बहराइच जिलेमें भारत-नेपाल सीमा के पास कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य के घने जंगलों में लगभग 45-50 वर्ष की आयु के नर हाथी का शव मिला है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

मुख्य बिंदु:

- **मौत का कारण:**
 - ◆ अधिकारियों का मानना है कि हाथी की मौत दो वयस्क हाथियों के बीच लड़ाई के कारण हो सकती है, क्योंकि घटनास्थल पर पैरों के निशान और टूटे हुए पेड़ पाए गए हैं।
- **हालिया वन्यजीव मौतें:**
 - ◆ इस घटना से पहले भी अभयारण्य में 12 वर्षीय नर बाघ और 7 वर्षीय नर तेंदुए की मौतें हो चुकी हैं। ये घटनाएँ **वन्यजीवों की सुरक्षा** को लेकर गंभीर चिंताओं का कारण बन रही हैं।

कतर्नियाघाट वन्यजीव अभयारण्य

- **भौगोलिक स्थिति:**
 - ◆ यह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में **ऊपरी गंगा के मैदान** में स्थित है, जो प्राकृतिक रूप से एक समृद्ध और विविध **पारिस्थितिकी तंत्र** को बनाए रखता है।
 - ◆ यह 400.6 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है।
- **संरक्षण:**
 - ◆ वर्ष 1987 में इसे '**प्रोजेक्ट टाइगर**' के दायरे में लाया गया और **किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य** और **दुधवा राष्ट्रीय उद्यान** के साथ मिलकर यह **दुधवा टाइगर रिज़र्व** बनाता है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी।
 - ◆ अभयारण्य में **चीतल, हिरण, जंगली सूअर, बाघ, हाथी और तेंदुए** आदि प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं।
 - ◆ यह घड़ियाल, बाघ, गैंडे, गंगा डॉल्फिन, दलदली हिरण, हिसपिड खरगोश, बंगाल फ्लोरिकन, सफेद पीठ वाले और लंबी चोंच वाले गिद्धों सहित कई लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है।
- **पारिस्थितिकी संरचना:**
 - ◆ यह क्षेत्र **मिश्रित पर्णपाती वन** से घिरा हुआ है, जिसमें साल और सागौन के जंगल, हरे-भरे घास के मैदान, असंख्य दलदल और आर्द्रभूमि शामिल हैं।
 - ◆ इस क्षेत्र में **गिरवा नदी बहती है**, जो पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करती है।

सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी**चर्चा में क्यों ?**

किसानों की आय बढ़ाने और फसल की बर्बादी को कम करने के उद्देश्य से **IIT कानपुर** ने एक नई **सौर निर्जलीकरण तकनीक (Solar Dehydration Technology)** विकसित की है।

मुख्य बिंदु

- **उद्देश्य:**
 - ◆ यह तकनीक **फलों और सब्जियों को सौर ऊर्जा** के माध्यम से सुखाने की सुविधा प्रदान करती है। यह एक कुशल और टिकाऊ तरीका है।
 - ◆ इसका उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाना और फसल की बर्बादी को कम करना है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट:

- ◆ किसान इस तकनीक का उपयोग करके अपनी फसलों को लंबे समय तक संरक्षित रख सकते हैं और उचित मूल्य मिलने पर उन्हें बेच सकते हैं।
- लाभ:
 - ◆ सोलर डिहाइड्रेशन एक पर्यावरण अनुकूल तरीका है, जो ऊर्जा की बचत करता है और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालता है।
 - ◆ सौर ऊर्जा का उपयोग करने से परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता कम होती है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम:
 - ◆ इस पहल के तहत हाल ही में 30 किसानों को सोलर डिहाइड्रेशन तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया है। किसानों को टमाटर के प्री-ट्रीटमेंट और सोलर ड्राईंग की लाइव डेमोंस्ट्रेशन दी गई, जिससे वे इस तकनीक को अपनी खेती में लागू कर सकेंगे।
- अन्य संस्थाओं का सहयोग:
 - ◆ इस प्रोजेक्ट में NABARD का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है।
 - ◆ इसके साथ ही, CSJM विश्वविद्यालय के फूड प्रोसेसिंग विभाग के साथ मिलकर इस तकनीक के लिये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) और गुणवत्ता प्रोटोकॉल तैयार किये गए हैं।

नाबार्ड (NABARD)

- नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिये एक शीर्ष बैंक है।
- इसकी स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिशों के आधार पर संसद के एक अधिनियम द्वारा 12 जुलाई, 1982 को की गई थी।
- इसका कार्य कृषि, लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्पों के संवर्द्धन और विकास के लिये ऋण प्रवाह को उपलब्ध कराना है।
- इसके साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य संबद्ध आर्थिक क्रियाओं को समर्थन प्रदान कर गाँवों का सतत् विकास करना है।

गंगा जल की शुद्धता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में महाकुंभ 2025 में गंगा जल की शुद्धता को लेकर संदेह दूर करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी की।

मुख्य बिंदु

मुद्दे के बारे में:

- गंगा जल की शुद्धता का दावा:
 - ◆ उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी कर एक वैज्ञानिक के हवाले से महाकुंभ में गंगा जल की शुद्धता के बारे में 'संदेह को दूर' करने का प्रयास किया और कहा कि नदी का जल 'क्षारीय जल की तरह' शुद्ध है।
 - उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के संदर्भ में यह विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें महाकुंभ में गंगा जल की गुणवत्ता पर संदेह जताया गया था।
- CPCB की रिपोर्ट:
 - CPCB की रिपोर्ट में कहा गया था कि महाकुंभ की शुरुआत में संगम पर पानी की जैविक ऑक्सीजन मांग (BOD) 3.94 मिलीग्राम प्रति लीटर थी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट:

- 14 जनवरी को यह 2.28 मिलीग्राम प्रति लीटर और 15 जनवरी को घटकर 1 मिलीग्राम प्रति लीटर हो गई।
- हालाँकि 24 जनवरी को BOD बढ़कर 4.08 मिलीग्राम प्रति लीटर हो गई और 29 जनवरी को यह 3.26 मिलीग्राम प्रति लीटर दर्ज की गई।
- डॉ. अजय कुमार सोनकर का शोध:
 - पद्मश्री डॉ. अजय कुमार सोनकर ने गंगा जल की पवित्रता को साबित करने के लिये वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ संदेह को खारिज किया।
 - उन्होंने महाकुंभ के विभिन्न प्रमुख स्नान घाटों से पानी के नमूने एकत्र किये और उनकी सूक्ष्म जाँच की।
 - उन्होंने पाया कि करोड़ों श्रद्धालुओं के स्नान के बावजूद गंगा जल में बैक्टीरिया की वृद्धि नहीं हुई।
 - पानी के **Ph स्तर** में भी कोई गिरावट नहीं देखी गई।
- प्राकृतिक वायरस की उपस्थिति:
 - गंगा जल में 1,100 प्रकार के प्राकृतिक वायरस, जिसे “**बैक्टीरियोफेज**” कहा जाता है, होते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करते हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB):

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में **जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974** के अंतर्गत **सितंबर 1974** को किया गया।
- इसके पश्चात् केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत शक्तियाँ व कार्य सौंपे गए।
- यह बोर्ड **पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986** के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएँ भी उपलब्ध कराता है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख कार्यों को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा **वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981** के तहत वर्णित किया गया है।

जैविक ऑक्सीजन मांग (Biological Oxygen Demand-BOD):

- ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में **कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन** के लिये आवश्यक होती है, वह **BOD** कहलाती है।
- जल प्रदूषण की मात्रा को BOD के माध्यम से मापा जाता है। परंतु BOD के माध्यम से केवल जैव अपघटक का पता चलता है साथ ही यह बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसलिये BOD को प्रदूषण मापन में प्रयोग नहीं किया जाता है।
- गौरतलब है कि उच्च स्तर के BOD का मतलब पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा को विघटित करने हेतु अत्यधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है।

फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया

चर्चा में क्यों ?

प्रयागराज में गंगा-यमुना में कई स्थानों पर **फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया** का स्तर काफी बढ़ गया है, जिसके कारण गंगा-यमुना का पानी नहाने लायक नहीं रहा है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट:

मुख्य बिंदु

- **CPCB की रिपोर्ट:**
 - **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)** की एक रिपोर्ट के अनुसार, **प्रयागराज संगम** पर फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का स्तर प्रति 100 मिलीलीटर जल में 2,500 यूनिट की सुरक्षित सीमा से कहीं अधिक है।
 - यह पानी पीने और नहाने के लिये पूरी तरह से अनुपयुक्त है, जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर असर हो सकता है।
- **NGT की टिप्पणी:**
 - इस मुद्दे पर **NGT (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल)** सुनवाई कर रहा है और संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी जा रही है।
 - महाकुंभ मेले के दौरान **सीवेज प्रबंधन योजना** को लेकर NGT पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश चुका है।

फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया के बारे में

- **परिचय**
 - ◆ यह **सूक्ष्मजीवों (Microorganism)** का एक संग्रह है जो, मुख्यतः गर्म रक्त वाले जानवरों एवं मनुष्यों द्वारा उत्सर्जित मल या अपशिष्ट में पाया जाता है।
 - ◆ इन्हें आमतौर पर पानी में संभावित प्रदूषण के संकेतक के रूप में माना जाता है।
 - ◆ अन्य कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया में **एस्चेरिचिया (Escherichia)**, **क्लेबसिएला (Klebsiella)** और **ई. कोली (E. coli)** आदि शामिल हैं।
 - ◆ जलस्रोत में इनकी उपस्थिति से जल में **हानिकारक रोगाणु**, जैसे- **वायरस, परजीवी** या अन्य संक्रामक बैक्टीरिया आदि का भी पता चलता है।

स्वास्थ्य पर प्रभाव

- इस बैक्टीरिया से अनेक बीमारियाँ जैसे **जठरांत्र संक्रमण**, **त्वचा और नेत्र संक्रमण**, **टाइफाइड**, **हेपेटाइटिस ए** और **श्वसन संबंधी समस्याएँ** हो सकती हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड:

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में **जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974** के अंतर्गत सितंबर 1974 को किया गया।
- इसके पश्चात् केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत शक्तियाँ व कार्य सौंपे गए।
- यह बोर्ड **पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986** के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएँ भी उपलब्ध कराता है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख कार्यों को **जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974** तथा **वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981** के तहत वर्णित किया गया है।

उपासना स्थल अधिनियम, 1991

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सांसद इकरा चौधरी ने **उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991** के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट:

मुख्य बिंदु

- गौरतलब है कि यह अधिनियम किसी भी पूजा/उपासना स्थल की स्थिति को उसी अवस्था में रोक देता/बनाए रखता है, जैसा कि वह 15 अगस्त, 1947 को थी।
- **उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991:**
 - ◆ यह पूजा स्थलों (**राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद** के मामले को छोड़कर, जिसका मामला पहले से ही अदालत में था) की “धार्मिक प्रकृति” को वर्ष 1947 की स्थिति के अनुरूप बनाए रखने का प्रयास करता है।
- **उद्देश्य:**
 - ◆ इस अधिनियम का उद्देश्य उपासना स्थलों की धार्मिक स्थिति को संरक्षित रखना तथा विभिन्न **धार्मिक संप्रदायों** के बीच या एक ही संप्रदाय के भीतर धर्मांतरण को रोकना है।
 - ◆ इस अधिनियम की धारा 3 के तहत पूजा स्थल या यहाँ तक कि उसके खंड को एक अलग धार्मिक संप्रदाय या एक ही धार्मिक संप्रदाय के अलग वर्ग के पूजा स्थल में परिवर्तित करने को प्रतिबंधित किया गया है।
 - ◆ इस अधिनियम की धारा 4(2) में कहा गया है कि पूजा स्थल की प्रकृति को परिवर्तित करने से संबंधित सभी मुकदमे, अपील या अन्य कार्रवाईयाँ (जो 15 अगस्त, 1947 को लंबित थी) इस अधिनियम के लागू होने के बाद समाप्त हो जाएंगी और ऐसे मामलों पर कोई नई कार्रवाई नहीं की जा सकती।
 - ◆ यह अधिनियम सरकार के लिये भी एक सकारात्मक दायित्व निर्धारित करता है कि वह हर पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र/प्रकृति को उसी प्रकार बनाए रखे जैसा कि वह स्वतंत्रता के समय था।
- **अपवाद:**
 - ◆ अयोध्या का विवादित स्थल (राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद) को इस अधिनियम से छूट दी गई थी। इसी छूट के कारण इस कानून के लागू होने के बाद भी अयोध्या मामले में मुकदमा आगे बढ़ सका।
- **इसके अलावा इस अधिनियम में कुछ अन्य मामलों को भी छूट दी गई:**
 - ◆ कोई भी पूजा स्थल जो ‘**प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल** अवशेष अधिनियम, 1958’ के तहत शामिल प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक या एक पुरातात्विक स्थल है।
 - ◆ ऐसे मुकदमे जिनका निस्तारण हो चुका है या जिन पर अंतिम फैसला दिया जा चुका है।
- **दंड:**
 - ◆ इस अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ अधिकतम तीन वर्ष के कारावास के दंड का प्रावधान है।
- **सर्वोच्च न्यायालय का मत:**
 - ◆ वर्ष 2019 में अयोध्या मामले के फैसले में **सर्वोच्च न्यायालय** की संवैधानिक पीठ ने इस कानून का उल्लेख करते हुए कहा कि यह संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को प्रकट करता है और इसकी प्रतिगामिता को सख्ती से प्रतिबंधित करता है।
- **याचिका में दिये गए तर्क:**
 - ◆ याचिका में इस अधिनियम को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह अधिनियम **धर्मनिरपेक्षता** का उल्लंघन करता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
कलासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट:

- ◆ इस याचिका में यह तर्क दिया गया है कि 15 अगस्त, 1947 की कट-ऑफ तिथि “मनमाना, तर्कहीन और पूर्वव्यापी” है तथा यह हिंदुओं, जैन, बौद्धों और सिखों को अपने “पूजा स्थलों” पर पुनः दावा करने के लिये अदालत जाने से रोकती है, जिन पर “कट्टरपंथी बर्बर आक्रमणकारियों” द्वारा “आक्रमण” कर “अतिक्रमण” कर लिया गया था।
- ◆ याचिका में यह तर्क दिया गया है कि केंद्र के पास “तीर्थस्थल” या “कब्रिस्तान” पर कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है, जो राज्य सूची के तहत आते हैं।
- ◆ हालाँकि सरकार के अनुसार, वह इस कानून को लागू करने के लिये **संघ सूची** की प्रविष्टि 97 के तहत अपनी **अवशिष्ट शक्ति** का उपयोग कर सकती है।
- ◆ संघ सूची की प्रविष्टि 97 केंद्र को उन विषयों पर कानून बनाने के लिये अवशिष्ट शक्ति प्रदान करती है जिन्हें (जिन विषयों को) तीनों में से किसी भी सूची में शामिल नहीं किया गया है।

महाकुंभ 2025 का समापन

चर्चा में क्यों ?

प्रयागराज में 13 जनवरी 2024 से शुरू हुए **महाकुंभ मेले** का 45 दिन बाद **26 फरवरी 2025** को **महाशिवरात्रि** के स्नान के पवित्र साथ समापन हो गया।

मुख्य बिंदु

- महाकुंभ मेला 2025 दुनिया का सबसे बड़ा मेला बन गया, जिसमें 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आए, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की आबादी से दोगुना है।
- दुनिया में कहीं भी इतनी बड़ी भीड़ पहले कभी नहीं देखी गई। महाकुंभ मेला क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम से 166 गुना बड़ा था।
- **समापन समारोह के बारे में:**
 - ◆ समापन समारोह संगम तट 27 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा महाकुंभ मेले के समापन की आधिकारिक घोषणा की गई।
 - ◆ मुख्यमंत्री ने महाकुंभ को ऐतिहासिक, दिव्य, भव्य, स्वच्छ, सुरक्षित और डिजिटल बनाने में योगदान देने वाले **कर्मचारियों और संस्थाओं को सम्मानित किया।**
- **प्रमुख घोषणाएँ:**
 - ◆ किसान आपदा योजना के तहत नाव संचालकों को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के समान आपदा सहायता मिलेगी, जिसके तहत दुर्भाग्यपूर्ण घटना की स्थिति में 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। जिन लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है, उन्हें इसके तहत कवर किया जाएगा।
 - ◆ जिन लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है, उन्हें **आयुष्मान भारत योजना** के तहत कवर किया जाएगा।
 - ◆ महाकुंभ ड्यूटी पर तैनात सफाई कर्मचारियों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को **10 हजार का अतिरिक्त बोनस मिलेगा।**
 - ◆ मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार एक निगम बनाने जा रही है जिसके माध्यम से वह प्रत्येक सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी और उन सभी श्रमिकों को 16,000 रुपये प्रति माह प्रदान करेगी जिन्हें न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही थी। यह राशि अप्रैल 2025 से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से उनके खाते में भेजी जाएगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट:

- कुंभ मेला 2025 के प्रमुख आकर्षण:
 - ◆ त्रिवेणी संगम: गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र संगम।
 - ◆ प्राचीन मंदिर: हनुमान मंदिर, अलोपी देवी मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर।
 - ◆ कलाग्राम: संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्थापित सांस्कृतिक गाँव, शिल्प, व्यंजन और संस्कृति से जुड़ी प्रदर्शनी।
 - ◆ अखाड़ा शिविर: साधु-साधकों का ध्यान, चर्चा और दार्शनिक आदान-प्रदान का केंद्र।
 - ◆ ड्रोन शो: उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा भव्य ड्रोन शो।
 - ◆ अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव: 16-18 फरवरी 2025 को 200 से अधिक पक्षियों का प्रदर्शन।
- महत्वपूर्ण पहल:
 - ◆ चिकित्सा सुविधाएं:
 - मेले के दौरान 133 एम्बुलेंस तैनात की गईं, जिनमें सात जल एम्बुलेंस और एक एयर एम्बुलेंस शामिल हैं।
 - जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दवाइयाँ।
- हरित पहल (मियावाकी वन):
 - ◆ पिछले दो वर्षों में प्रयागराज में मियावाकी तकनीक का उपयोग करके लगभग 56,000 वर्ग मीटर घने जंगल बनाए गए।
 - ◆ बसवार डंपिंग यार्ड को हरित क्षेत्र में परिवर्तित किया गया।
 - ◆ ट्रेश स्किमर मशीनों से नदियों की सफाई।

कुंभ मेले के बारे में

- वर्ष 2025 में महाकुंभ मेला प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया है, जिसमें 66.30 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए।
- 'कुंभ' शब्द की उत्पत्ति 'कुंभक' (अमरता के अमृत का पवित्र घड़ा) धातु से हुई है।
- पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्द्धन ने प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन प्रारंभ किया।
- यह तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम है जिसके दौरान प्रतिभागी पवित्र नदी में स्नान या डुबकी लगाते हैं। यह समागम 4 अलग-अलग जगहों पर होता है, अर्थात्:
 - ◆ हरिद्वार में गंगा के तट पर।
 - ◆ उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर।
 - ◆ नासिक में गोदावरी (दक्षिण गंगा) के तट पर।
 - ◆ प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक अदृश्य सरस्वती के संगम पर

कुंभ के विभिन्न प्रकार:

- कुंभ मेला 12 वर्षों में 4 बार मनाया जाता है।
- हरिद्वार और प्रयागराज में अर्द्धकुंभ मेला हर छठे वर्ष आयोजित किया जाता है।
- महाकुंभ मेला 144 वर्षों (12 'पूर्ण कुंभ मेलों' के बाद) के बाद प्रयाग में मनाया जाता है।
- प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ (जनवरी-फरवरी) महीने में माघ कुंभ मनाया जाता है

यूनेस्को की सूची में शामिल

- यूनेस्को ने कुंभ मेला को 2017 में अपनी "मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत" की सूची में शामिल किया।



दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप

